

पैन पॉवर



हिंदी दैनिक समाचार पत्र

वर्ष - 1 अंक - 8

शनिवार, जुलाई 11, 2026

विशाखापट्टनम

संपादक: गंट्यादा अप्पाराव

पृष्ठों. 4मूल्य. 1रु

दक्षिण कोरिया दौरे के छठे दिन मंत्री नारा लोकेश की बैठकों का दौर

आंध्र प्रदेश में निवेश आकर्षित करना लक्ष्य

दक्षिण कोरिया, अमरावती, 10 जुलाई: दक्षिण कोरिया दौरे के तहत छठे दिन आंध्र प्रदेश के मंत्री छंतं स्वामी ने CUCKOO Electronics के संचालन प्रमुख (एचओडी) चो हान चुल से मुलाकात की।

बैठक के दौरान लोकेश ने कंपनी से आंध्र प्रदेश में घरेलू उपकरण (होम अप्लायंसेज) निर्माण इकाई स्थापित करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि राज्य के तप ब्यजल में पहले से ही एक विकसित होम अप्लायंसेज क्लस्टर मौजूद है, जहां कई प्रमुख कंपनियां अपनी गतिविधियां संचालित कर रही हैं।

लोकेश ने कहा कि भारत में निर्मित होने वाले एयर कंडीशनरों का लगभग 40 प्रतिशत और टेलीविजनों का 35 प्रतिशत उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। उन्होंने यह भी बताया कि उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप कुशल कार्यबल राज्य में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तथा यहां से दक्षिण-पूर्व एशियाई और मध्य-पूर्वी देशों को निर्यात करना भी बेहद आसान है।

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि दक्षिण भारत में एयर



कंडीशनरों की मांग काफी अधिक है। इस पर कुकू इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार के प्रस्तावों पर सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया।

इसी दौरे के दौरान लोकेश ने एक ऑटो मोटिव पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) से भी अलग से मुलाकात की। उन्होंने कंपनी से श्री सिटी में मोटिव लिंक परियोजना स्थापित करने तथा इलेक्ट्रिक वाहन

(ईवी) पुर्जों और इंटीग्रेटेड मॉड्यूल निर्माण इकाइयों में निवेश करने का आग्रह किया। मंत्री ने बताया कि श्री सिटी में उद्योगों की स्थापना के लिए आवश्यक सभी बुनियादी सुविधाएं, जैसे बिजली, पानी और लॉजिस्टिक्स, पहले से उपलब्ध हैं। उन्होंने रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में भी निवेश का आह्वान किया तथा कोरियाई कंपनियों के सहयोग से मोटिव लिंक परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव रखा।

सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर कैबिनेट गंभीर, कड़े कानून बनाने के निर्देश: मंत्री पार्थसारथी



(पेन पॉवर न्यूज): अमरावती, 10 जुलाई: आंध्र प्रदेश के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री के. पार्थसारथी ने कहा कि कैबिनेट ने चिंता व्यक्त की है कि सोशल मीडिया समाज के लिए लाभकारी होने के साथ-साथ गंभीर नुकसान पहुंचाने वाली “बीमारी” का रूप भी लेता जा रहा है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट में इस बात पर चर्चा हुई कि सोशल मीडिया का लोगों की सोच और शासन व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव

पड़ रहा है। शुक्रवार को वेलगापुडी स्थित सचिवालय में मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए मंत्री पार्थसारथी ने बताया कि पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) हरीश कुमार गुप्ता ने दुनिया के विभिन्न देशों में सोशल मीडिया को नियंत्रित करने के लिए लागू किए गए कड़े कानूनों पर प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि पारंपरिक

मीडिया में जो जवाबदेही और नैतिक मूल्य होते हैं, वे सोशल मीडिया में दिखाई नहीं देते। मंत्री ने सोशल मीडिया पर बढ़ते चरित्र हनन, सरकार के खिलाफ झूठे प्रचार और गलत सूचनाओं को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग राजनीतिक विरोधियों पर हमले और झूठे प्रचार के लिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल ऐसे कार्यों को आर्थिक सहयोग प्रदान कर रहे हैं। पार्थसारथी ने बताया कि डीजीपी और पुलिस अधिकारियों ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर कैबिनेट को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी। बैठक में विदेशों में लागू सोशल मीडिया कानूनों और भारत के सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कानून की कमियों पर भी व्यापक चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री

चंद्रबाबू नायडू ने स्पष्ट किया है कि सरकार महिलाओं और बालिकाओं का अपमान करने वाली पोस्टों, चरित्र हनन तथा सरकार के खिलाफ झूठे प्रचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर कानूनों को और मजबूत बनाने तथा कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कैबिनेट ने राज्य स्तरीय सोशल मीडिया रिसर्प्स सेल स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया दुरुपयोग से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए राज्य स्तरीय टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री पार्थसारथी ने बताया कि नफरत फैलाने वाले अभियान और चरित्र हनन में शामिल सोशल मीडिया हैंडलर्स की पहचान के लिए आधुनिक फोरेंसिक उपकरण उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया

है। मुख्यमंत्री ने सभी थाना प्रभारियों (एसएचओ) को सोशल मीडिया दुरुपयोग मामलों से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण देने का सुझाव भी दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने आवश्यकता पड़ने पर साइबर जांच में विशेषज्ञता रखने वाले लोक अभियोजकों की नियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, सोशल मीडिया दुरुपयोग पर नियंत्रण के लिए देश और विदेश में अपनाई जा रही सर्वोत्तम व्यवस्थाओं का अध्ययन करने हेतु मंत्रियों के समूह (जीओएम) का गठन करने का भी निर्देश दिया है। मंत्री ने बताया कि कैबिनेट में राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और सतत विकास हासिल करने पर भी व्यापक चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं के निरंतर क्रियान्वयन के लिए राज्य की आर्थिक मजबूती अत्यंत आवश्यक है।

आपत्तिजनक टिप्पणियों को बर्दाश्त न करें एपी कैबिनेट का पुलिस विभाग को निर्देश

(पेन पॉवर न्यूज): अमरावती, 10 जुलाई: आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सोशल मीडिया के मुद्दे पर गंभीर चर्चा हुई। शुक्रवार को मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और अन्य पुलिस अधिकारियों ने सोशल मीडिया से जुड़े मामलों पर पावरपॉइंट प्रस्तुति दी।

मंत्रियों ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन वीडियो और पोस्टों पर कड़ी आपत्ति जताई, जिनमें सरकार के खिलाफ प्रचार और नेताओं को अपमानित करने वाली सामग्री होने की बात कही गई। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करने पर जोर देते हुए कैबिनेट ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि आपत्तिजनक टिप्पणियों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त न किया जाए। इसके लिए तत्काल एक विशेष टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश दिए गए। आवश्यकता पड़ने पर विभाग के बाहर से भी कर्मियों की नियुक्ति करने का सुझाव दिया गया। एपी कैबिनेट ने कानूनी जटिलताओं से बचने के लिए नए लोक अभियोजकों (पब्लिक प्रॉसिक्यूटर) की नियुक्ति करने का भी निर्देश दिया। बताया गया कि मंत्रियों ने अधिकारियों से कहा कि सरकार के खिलाफ गद्दी गई कहानियों, झूठी सूचनाओं और

तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने के मामलों को किसी भी हाल में नजरअंदाज न किया जाए। कैबिनेट ने स्पष्ट किया कि पुलिस तंत्र आज से ही सोशल मीडिया की निगरानी पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करे। साथ ही, सरकार द्वारा पहले से गठित सोशल मीडिया संबंधी कैबिनेट उपसमिति में भी इस विषय पर चर्चा करने का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मंत्रियों से कहा कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के नेता राज्य में हो रहे विकास और कल्याणकारी कार्यों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए नई रणनीति अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे जानबूझकर विधायकों को उकसा रहे हैं और सत्तारूढ़ दल के विधायकों को ऐसी उकसावों पर प्रतिक्रिया न देने की सलाह दी। उन्होंने चेतावनी दी कि वाईएसआरसीपी उन्हें जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है, इसलिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान अनंतपुर सहित अन्य जिलों में हुई घटनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने मंत्रियों को विकास और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनता को विस्तार से बताने का निर्देश दिया। साथ ही, जिला दौरों के दौरान प्रभारी मंत्रियों को स्थानीय विधायकों के साथ समन्वय स्थापित करने तथा राजस्व एवं अन्य जनसमस्याओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए।

प्रश्ना रावण, प्रकाश राज और जड़ा श्रवण पेड आर्टिस्ट हैं: जनसेना विधायक

(पेन पॉवर न्यूज): विशाखापत्तनम, 10 जुलाई: जनसेना पार्टी के विधायक सुंदरपु विजय कुमार ने आरोप लगाया कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) राज्य में धार्मिक तनाव पैदा करने की साजिश रच रही है। शुक्रवार को मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने लोगों से वाईएसआरसीपी की कथित साजिशों पर ध्यान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सनातन धर्म और हिंदुत्व के खिलाफ मनमानी टिप्पणियां कर रहे हैं। विजय कुमार ने आरोप लगाया कि जड़ा श्रवण ने हाल ही में एलुरु में एक सभा आयोजित कर उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण

को निशाना बनाया। उन्होंने सवाल किया कि यूट्यूबर प्रश्ना रावण और अभिनेता चॉवीं रंर को सनातन धर्म का वास्तविक अर्थ पता भी है या नहीं। उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि प्रश्ना रावण, प्रकाश राज और जड़ा श्रवण “पेड आर्टिस्ट” हैं। जनसेना विधायक ने कहा कि देश में संघर्ष पैदा करने की साजिशें चल रही हैं। उन्होंने पुलिस से राज्य में विभिन्न धर्मों के बीच वैमनस्य फैलाने की कथित साजिश का पर्दाफाश करने की मांग की। उन्होंने पूरे मामले की विस्तृत जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की। विजय कुमार ने यह भी कहा कि आंध्र प्रदेश में

धार्मिक संघर्ष पैदा करने की कोशिश करने वालों के ताड़पल्ली से जुड़े कथित संबंधों को उजागर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में सभी धर्मों और जातियों का सम्मान किया जाता है। जड़ा श्रवण द्वारा कथित रूप से यह कहे जाने पर कि उन्होंने जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ २25 करोड़ खर्च किए, विजय कुमार ने मांग की कि वह बताएं कि यह पैसा उन्हें कहाँ से मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग शांतिपूर्ण माहौल वाले देश को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं और चेतावनी दी कि सनातन धर्म तथा हिंदुत्व के खिलाफ किसी भी कथित साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

लूट के प्रतीक जगन, निवेश और उद्योगों के प्रतीक चंद्रबाबू: पट्टाभि

अमरावती, 10 जुलाई: स्वच्छ आंध्र कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष कोम्मारेड्डी पट्टाभिराम ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री Y- S- Jagan Mohan Reddy पर तीखा हमला बोला। शुक्रवार को मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि जगन ने अपने पिता के राजनीतिक प्रभाव का उपयोग करते हुए उद्योगों को भूमि आवंटन के नाम पर कथित 'विशेष प्रोत्सव' व्यवस्था के जरिए करोड़ों रुपये कमाए। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणी स्टील्स के नाम पर रायलसीमा के युवाओं को रोजगार देने का सपना दिखाया गया, लेकिन यह परियोजना कथित रूप से बड़े पैमाने पर आर्थिक लाभ कमाने का माध्यम बन गई।

पट्टाभिराम ने आरोप लगाया कि ब्राह्मणी स्टील्स को लगभग 14,000 एकड़ सार्वजनिक और सरकारी भूमि बेहद कम कीमत पर आवंटित की गई। उन्होंने कहा कि बाद में इसी भूमि को लगभग 350 करोड़ के लिए गिरवी रखकर बड़े वित्तीय अनियमितताओं को अंजाम दिया गया। उन्होंने सवाल किया कि क्या यह सच नहीं है कि रेड गोल्ड एंटरप्राइजेज और आरआर ग्लोबल एंटरप्राइजेज से २44 करोड़ जगति पब्लिकेशनस तथा २30 करोड़ इंदिरा टेलीविजन को भेजे गए थे। उनका आरोप था कि करोड़ों रुपये मिलने के बावजूद ब्राह्मणी स्टील्स परियोजना में एक भी ईंट नहीं रखी गई। पट्टाभिराम ने याद दिलाया कि 10 जून 2007 को ब्राह्मणी स्टील्स

के शिलान्यास कार्यक्रम का नेतृत्व स्वयं जगन ने किया था। उन्होंने यह भी कहा कि ओबुलापुरम खदान मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने गंभीर अनियमितताओं की ओर संकेत किया था। इसके बावजूद, उनके अनुसार, अगस्त 2022 में जगन सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एक हलफनामा दाखिल कर ओबुलापुरम खदानों पर कोई आपत्ति न होने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार ने उन 14,000 एकड़ सरकारी भूमि को वापस अपने कब्जे में ले लिया है, जिसे उनके अनुसार इस मामले में नुकसान पहुंचा था। पट्टाभिराम ने दावा किया कि जहां पहले उद्योगों के नाम पर लूट हुई, वहीं वर्तमान गठबंधन सरकार उद्योगों को आकर्षित कर



युवाओं के लिए रोजगार क्रांति ला रही है। उन्होंने कहा कि आ से शुरू हुई औद्योगिक प्रगति अब Google] Tata Consultancy Services (टीसीएस), Cognizant और ArcelorMittal जैसी

वैश्विक कंपनियों के निवेश से आगे बढ़ रही है। अंत में पट्टाभिराम ने कहा कि यदि जगन “लूट” के प्रतीक हैं, तो मुख्यमंत्री N- Chandrababu Naidu निवेश, उद्योग और रोजगार के प्रतीक हैं।

संपादकीय

पश्चिम एशिया में फिर बढ़ा तनाव

एक ओर ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार का आयोजन हो रहा था, वहीं दूसरी ओर होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजर रहे तीन जहाजों पर हमले के बाद अमेरिका और ईरान के बीच परस्पर हमले फिर शुरू हो गए। अमेरिका ने आरोप लगाया कि होर्मुज जलडमरूमध्य में हुए नए हमले के पीछे ईरानी सेना का हाथ है। इस संदर्भ में तुर्की की राजधानी अंकारा में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को पत्रकारों से कहा कि अब ईरान के साथ कोई और बातचीत नहीं होगी। उन्होंने ईरानियों की तीखी आलोचना करते हुए उन्हें छलपूर्ण और अविश्वसनीय बताया।

होर्मुज जलडमरूमध्य में तीन वाणिज्यिक जहाजों पर हमले के कुछ ही घंटों के भीतर अमेरिका ने ईरानी सैन्य ठिकानों और बंदरगाह अवसंरचना पर हमले किए। अमेरिकी मीडिया संस्थान एक्सियोस के अनुसार, इन हमलों में ईरान की वायु रक्षा प्रणालियां, तटीय निगरानी तंत्र, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, एंटी-शिप क्रूज मिसाइल ठिकाने, ड्रोन लॉन्च साइट्स और बंदरगाहों को निशाना बनाया गया।

बंदर अब्बास, सीरिक और केशम द्वीप के बंदरगाह शहरों में विस्फोट हुए। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में स्थित 85 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर मिसाइलें दागीं। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बहरीन में अमेरिकी पांचवें बेड़े तथा कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस सहित 85 महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को लक्ष्य बनाने का दावा किया। प्च्छ ने यह भी कहा कि उसने बुशेहर क्षेत्र में अमेरिका के अत्याधुनिक डफ—9 ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी दावा किया कि उसने ईरान में 80 से अधिक लक्ष्यों पर अत्यंत सटीक हमले किए। रिपोर्टों के अनुसार, ट्रंप ने तुर्की में नाटो सम्मेलन के दौरान ही ईरान पर नवीनतम हमलों का आदेश दिया था। इन ताजा हमलों ने पिछले महीने हुए अमेरिका-ईरान अंतरिम समझौते को संकट में डाल दिया है। दोनों देश एक-दूसरे पर समझौते की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगा रहे हैं। हमलों के बाद अमेरिका ने ईरान को दी गई तेल बिक्री की अनुमति भी रद्द कर दी, जो दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के प्रयास का हिस्सा थी।

ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के इस निर्णय की कड़ी निंदा की और इसे इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद—10 का उल्लंघन बताया। प्च्छ ने आरोप लगाया कि खामेनेई के अंतिम संस्कार के दौरान अमेरिका अपने ऐतिहासिक एजेंडे को छिपाने का प्रयास कर रहा है। ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकष्टि गालिबाफ ने सोशल मीडिया पर चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका की धमकियों और दबाव का युग समाप्त हो चुका है तथा तेहरान अब किसी भी दबाव के सामने झुकने वाला नहीं है। ट्रंप द्वारा ईरान के साथ समझौते को खारिज किए जाने के बाद भारतीय शेयर बाजारों में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स और निपटी में 2 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई। इन अप्रत्याशित घटनाक्रमों से निवेशकों की लगभग 8 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति घट गई। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण तेल और गैस क्षेत्र के सूचकांकों में भी लगभग 1.5 प्रतिशत की गिरावट जारी है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें फिर उछल गई हैं। ब्रेंट क्रूड का भाव 78.35 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया। भारतीय रुपया भी और कमजोर हुआ तथा बुधवार के कारोबार में 20 पैसे की गिरावट के साथ 95.16 के स्तर पर कारोबार करता दिखा। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए एक और तेल आपूर्ति संकट तथा कीमतों में भारी वृद्धि की आशंका व्यक्त की जा रही है। अंतरिम समझौते के समाप्त होने के बाद कई देशों को चिंता है कि समुद्री मार्ग फिर बाधित हो सकते हैं और वे तेल संकट में फंस सकते हैं।

अमेरिका स्वयं भी ऊर्जा आपूर्ति संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहा है। उसकी दैनिक आवश्यकता लगभग 1.25 करोड़ बैरल कच्चे तेल की बताई जा रही है, जबकि मौजूदा भंडार केवल जुलाई के मध्य तक के लिए पर्याप्त हैं। इसलिए युद्ध रुकने पर ही अमेरिका को तेल की नियमित आपूर्ति संभव हो पाएगी। आलोचकों का कहना है कि ट्रंप की कठोर नीति इस समस्या को और जटिल बना रही है। बराक ओबामा के कार्यकाल में वर्ष 2015 में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु अप्रसार सहित कई मुद्दों पर समझौता हुआ था, लेकिन ट्रंप के सत्ता में आने के बाद उस समझौते को रद्द कर दिया गया। तब दावा किया गया था कि अमेरिका इससे बेहतर समझौता करेगा। हालांकि अब तक कई दौर की वार्ताएं होने के बावजूद हमले नहीं रुके हैं।

इन घटनाओं के कारण पश्चिम एशिया का भविष्य अनिश्चित दिखाई दे रहा है। अमेरिका के साथ रक्षा समझौते रखने वाले बहरीन जैसे देशों में भी चिंता बढ़ गई है कि अमेरिकी सैन्य अड्डे उन्हें सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं या उन्हें हमलों का लक्ष्य बना रहे हैं। इसी कारण कई देश अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आपसी बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका पर इन देशों की एकजुटता को रोकने की कोशिश करने का आरोप लगाया जा रहा है। परमाणु शक्ति संपन्न पाकिस्तान भी इन वार्ताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। चीन और रूस इन देशों का समर्थन कर रहे हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह घटनाक्रम अमेरिकी प्रभुत्व के खिलाफ उभरते प्रतिरोध का संकेत हो सकता है।

एआई : भारतीय रेलवे के लिए गेम चेंजर

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आज विश्वभर में कार्य करने के तरीकों को तेजी से बदल रही है। विपणन, डेटा विश्लेषण, खरीद प्रक्रिया से लेकर दैनिक संचालन तक लगभग हर क्षेत्र में AI का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित बनाकर, अनावश्यक प्रक्रियाओं को कम करके तथा त्वरित एवं सटीक विश्लेषण उपलब्ध कराकर AI संस्थाओं की कार्यकुशलता, उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि कर रही है। विश्व के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक भारतीय रेल भी AI के व्यापक उपयोग से अपनी परिचालन, अनुरक्षण तथा वाणिज्यिक गतिविधियों को नई ऊँचाइयों तक पहुँचा सकती है। रेलवे में AI का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग पूर्वानुमान आधारित अनुरक्षण (Predictive Maintenance) के क्षेत्र में हो सकता है। अत्याधुनिक सेंसर और AI तकनीक की सहायता से रेलवे पटरियों में आई दरारें, ट्रैक फिटिंग्स की कमी, पुलों की संरचनात्मक कमजोरियाँ,

विशेषकर एग्रोच क्षेत्र की स्थिति तथा पटरियों या अंडरपास के आसपास बढ़ते जलस्तर जैसी संभावित समस्याओं का समय रहते पता लगाया जा सकता है। इससे किसी भी बड़ी तकनीकी खराबी या दुर्घटना की संभावना को पहले ही कम किया जा सकता है। IC केवल दोषों की पहचान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उपलब्ध आँकड़ों का विश्लेषण कर अनुरक्षण कार्यों की बेहतर योजना बनाने, स्पेयर पार्ट्स एवं सामग्री के कुशल प्रबंधन, लागत नियंत्रण तथा समय पर आवश्यक हस्तक्षेप सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इससे डिपो में निरीक्षण एवं अनुरक्षण में लगने वाला समय कम होगा, वैगनों और कोचों का टर्नअराउंड समय घटेगा तथा समय उत्पादकता में उल्लेखनीय सुधार होगा।

AI रेलवे कर्मचारियों के लिए एक प्रभावी ज्ञान भंडार (Knowledge Repository) के रूप में भी कार्य कर सकता है। अनुरक्षण डिपो तथा ट्रेन संचालन से जुड़े कर्मचारियों को विभिन्न तकनीकी दोषों के

समाधान, मानक प्रक्रियाओं तथा अधिकृत मैनुअलों के अनुरूप त्वरित मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा सकता है, जिससे निर्णय लेने की गति और गुणवत्ता दोनों में सुधार होगा।

ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में भी AI अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। यह लोको पायलटों को सबसे उपयुक्त थ्रॉटलिंग एवं ईंधन उपयोग संबंधी सुझाव देकर ईंधन की खपत को कम करने, ऊर्जा दक्षता बढ़ाने तथा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने में सहायता कर सकता है। इसके अतिरिक्त, लोकोमोटिव तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थापित AI & सक्षम कैमरे एवं लेजर स्कैनर ओवरहेड विद्युत उपकरणों का वास्तविक समय में निरीक्षण कर सकते हैं, मानव रहित समपार फाटकों या लेवल क्रॉसिंग पर ट्रैक अवरोधों का पता लगा सकते हैं तथा विद्युतीकृत क्षेत्रों में अनधिकृत प्रवेश या मानव गतिविधियों की तुरंत सूचना संबंधित अधिकारियों तक पहुँचा सकते हैं। यात्रियों के लिए भी ।। यात्रा अनुभव को अधिक सरल, सुरक्षित और सुविधाजनक बना

सकता है। एकीकृत AI आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से यात्री अपने कोच, प्रतीक्षालय, विश्राम गृह, चिकित्सा सुविधाओं तथा ऑनबोर्ड स्टाफ की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। डिजिटल इमेजिंग एवं IC की सहायता से प्लेटफॉर्मों और ट्रेनों में भीड़ का वास्तविक समय में विश्लेषण कर प्रभावी भीड़ प्रबंधन, संसाधनों की बेहतर योजना तथा भविष्य के अवसंरचनात्मक विकास में सहायता मिलेगी। हालाँकि भारतीय रेल ने अपनी परिसंपत्तियों के आधुनिकीकरण की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है, फिर भी वैश्विक स्तर के दक्ष, प्रभावी और किफायती रेल तंत्र के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए अभी लंबा सफर तय करना बाकी है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए रेल परिचालन की मुख्यधारा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का सुनियोजित एवं व्यापक एकीकरण अत्यंत आवश्यक है। AI का विवेकपूर्ण और प्रभावी उपयोग भारतीय रेल को अधिक सुरक्षित, स्मार्ट, टिकाऊ तथा वास्तविक अर्थों में यात्री—केंद्रित बना सकता है, जिससे वह भविष्य की



लेखिका – डॉ. जीनिया गुप्ता

चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार होगी। AI केवल एक नई तकनीक नहीं, बल्कि भारतीय रेल के भविष्य को नई

दिशा देने वाला वास्तविक ‘गेम चेंजर’ सिद्ध हो सकता है। लेखिका 2009 बैच की भारतीय रेलवे ट्रेफिक सेवा (प्ट्से) की अधिकारी हैं।

न्यायिक सेवाओं में नेतृत्व के लिए डॉ. श्रीनिवास राव कावेटी को अंतरराष्ट्रीय सम्मान मानवीय सेवाओं के लिए डॉ. कावेटी को कनाडा लेगेसी ह्यूमैनिटेरियन अवॉर्ड प्रदान तेलंगाना के एक विधि विशेषज्ञ को अंतरराष्ट्रीय पहचान



हैदराबाद: डॉ. श्रीनिवास राव कावेटी, जो कावेटी लॉ फर्म के संस्थापक एवं प्रबंध अधिवक्ता तथा रैमसेयर एंड एसोसिएट्स पी.सी. में उपाध्यक्ष हैं, को ‘ग्लोबल एडवोकेसी के लिए कनाडा लेगेसी ह्यूमैनिटेरियन अवॉर्ड’ से सम्मानित किया गया है। उन्हें विधि व्यवसाय, मानवाधिकार संरक्षण, मानवीय सेवाओं तथा अंतरराष्ट्रीय विधिक नेतृत्व में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए अनेक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं। इन सम्मानों में सबसे उल्लेखनीय नेल्सन मंडेला अवॉर्ड है, जो उन्हें यूनाइटेड किंगडम के ऑक्सफोर्ड में प्रदान किया गया। यह सम्मान उन्हें मानवाधिकारों

की रक्षा, कानूनी सुधारों तथा समाज के सभी वर्गों के लिए न्याय को सुलभ बनाने में उनके योगदान के लिए दिया गया। साथ ही यह उनके द्वारा अपनी कानूनी सेवाओं के माध्यम से समानता, संवैधानिक मूल्यों और कानून के शासन को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को भी मान्यता देता है।

डॉ. कावेटी को अंतरराष्ट्रीय विधि

क क्षेत्र में उनके नेतृत्व तथा व्यक्तियों, व्यवसायों और संस्थानों द्वारा सामना की जाने वाली जटिल अंतरराष्ट्रीय कानूनी समस्याओं के समाधान उपलब्ध

कराने के लिए इंटरनेशनल काउंसिल लीडरशिप अवॉर्ड से भी सम्मानित किया गया है।



मानवाधिकारों, विधिक शिक्षा और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए उन्हें ‘ग्लोबल ह्यूमन राइट्स लीडरशिप अवॉर्ड’ भी प्रदान किया गया।

ये पुरस्कार कानूनी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने और अंतरराष्ट्रीय मंचों के माध्यम से वंचित समुदायों का समर्थन करने के उनके निरंतर प्रयासों को मान्यता देते हैं। विधि व्यवसाय में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के सम्मान में उन्हें विश्वप्रसिद्ध मार्किवस हूज नूनिदेशिका में भी शामिल किया गया। यह सम्मान उनके असाधारण पेशेवर योगदान

और विधि क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करता है। डॉ. कावेटी के कार्यों ने अंतरराष्ट्रीय मीडिया का भी ध्यान आकर्षित किया है। हाल ही में एमएसएन ने अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से परे कानूनी मामलों के प्रबंधन में उनके नेतृत्व को प्रमुखता से प्रकाशित किया और वैश्विक विधिक समुदाय में उनके बढ़ते प्रभाव की सराहना की। इसी प्रकार, यूएसए न्यूज ने भी उनके पेशेवर योगदान और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानूनी सेवाएं प्रदान करने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को विशेष रूप से प्रकाशित किया।

इन सम्मानों की श्रृंखला में एक और उपलब्धि जोड़ते हुए, डॉ. कावेटी को लंदन स्थित इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ज्यूरिस्ट्स की सदस्यता भी प्रदान की गई। यह विधि व्यवसाय के प्रति उनकी निरंतर सेवा और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से न्याय को आगे बढ़ाने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

डॉ. श्रीनिवास कावेटी को मार्किवस की मान्यता प्राप्त तेलंगाना के अंतरराष्ट्रीय वकील डॉ. श्रीनिवास कावेटी को मार्किवस हूज नू द्वारा सम्मानित किया गया है। यह एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित जीवनी निर्देशिका है, जो विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट पेशेवर उपलब्धियों और योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करती है। मूल रूप से करीमनगर के निवासी डॉ. कावेटी ने अपनी शिक्षा हैदराबाद में पूरी की। अंतरराष्ट्रीय विधिक क्षेत्र में तीन दशकों से अधिक की सेवा के साथ, वह वर्तमान में न्यूयॉर्क स्थित कावेटी लॉ फर्म के संस्थापक एवं प्रबंध अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हैं। इसके अलावा, वह न्यूयॉर्क की ‘रैमसेयर एंड एसोसिएट्स पी. सी.’ में भी वरिष्ठ नेतृत्व की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं।

उनकी कानूनी सेवाएं संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, भारत, कनाडा और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई देशों तक विस्तारित हैं। उन्होंने आव्रजन कानून, अंतरराष्ट्रीय कानून, कॉर्पोरेट कानून, वाद-विवाद, मध्यस्थता, पारिवारिक कानून और रियल एस्टेट कानून जैसे क्षेत्रों में व्यापक अनुभव प्राप्त किया है। भारत में अपनी विधि शिक्षा पूरी करने के बाद, डॉ. कावेटी ने ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरराष्ट्रीय व्यापार, वाणिज्य और कराधान कानून में मास्टर ऑफ लॉज (एल.एल.एम.) की उपाधि प्राप्त की। बाद में उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में सॉलिसिटर के रूप में योग्यता हासिल की। इसके पश्चात, संयुक्त राज्य अमेरिका में उच्च विधिक अध्ययन के दौरान उन्होंने कानून में पीएच.डी. की उपाधि प्राप्त की, जिसमें उनका विशेष शोध क्षेत्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता और विधिक मुकदमेबाजी था। उन्हें प्राप्त प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सम्मानों में नेल्सन मंडेला अवॉर्ड, ग्लोबल ह्यूमन राइट्स लीडरशिप अवॉर्ड तथा इंटरनेशनल काउंसिल लीडरशिप अवॉर्ड 2024 शामिल हैं।

नव नियुक्त राजपत्रित प्रधानाध्यापिका का सम्मान



गंगावरम, 10 जुलाई: यूनाइटेड टीचर्स फेडरेशन की गंगावरम मंडल इकाई ने जनजातीय कल्याण आश्रम बालिका उच्च विद्यालय की नव नियुक्त राजपत्रित प्रधानाध्यापिका चेन्नाडा चिन्ना सत्यवती का सम्मान किया। सत्यवती ने वर्ष 2014 से 2016 तक इसी विद्यालय में हिंदी स्कूल असिस्टेंट के रूप में सेवाएं दी थीं। यूटीएफ नेताओं ने शिक्षा के क्षेत्र में उनके समर्पण की सराहना करते हुए उनके सफल कार्यकाल और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम में शिक्षक एवं यूटीएफ पदाधिकारी उपस्थित रहे।

दूरदराज आदिवासी गांवों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी



रम्पचोडावरम, 10 जुलाई: पोलावरम जिला कलेक्टर के, दिनेश कुमार ने कहा कि गुर्तुडु मंडल के कानीवाडा पंचायत के दूरदराज आदिवासी गांवों में सड़क, पेयजल, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने “एक माहदृएक विधानसभा क्षेत्रदृचार गांव भ्रमण” कार्यक्रम के तहत कानीवाडा और कोंडा वेजुवाडा गांवों का दौरा कर लोगों की समस्याएं सुनीं तथा संबंधित अधिकारियों को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। कलेक्टर ने मानसून के दौरान मौसमी बीमारियों की रोकथाम, गर्भवती महिलाओं व बच्चों के स्वास्थ्य, रोजगार गारंटी कार्यों, अधुरी सरकारी इमारतों को पूरा करने, रबर किसानों के लिए प्रशिक्षण तथा मतदाता सूची संशोधन और भूमि पुनः सर्वेक्षण कार्यों में तेजी लाने पर भी जोर दिया।

गूगल डेटा सेंटर परियोजना के लिए हुए समझौते रद्द करने की मांग, सीपीआई ने चलाया जनजागरण अभियान

विशाखापट्टनम, पेन पॉवर, 10 जुलाई : भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) ने आंध्र प्रदेश सरकार से गूगल डेटा सेंटर परियोजना के लिए किए गए भूमि आवंटन समझौतों को तत्काल रद्द करने की मांग की है। पार्टी का आरोप है कि प्रस्तावित परियोजना से पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा तथा विशाखापट्टनम शहर में पेयजल संकट और गंभीर हो सकता है। शुक्रवार सुबह 6:00 बजे से 8:00 बजे तक अरिलोवा स्किड डेवलपमेंट सेंटर के समीप मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों के बीच सीपीआई नेताओं ने जनजागरण अभियान चलाते हुए पर्चे वितरित किए। इस अवसर पर सीपीआई जिला सचिव शेख रहीमान ने कहा कि राज्य में गठबंधन सरकार बनने के बाद बड़े कॉरपोरेट

समूहों को रियायती दरों पर मूल्यवान सरकारी भूमि आवंटित की जा रही है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचने की आशंका है। उन्होंने आरोप लगाया कि सेंट्रल जेल से मुदसलौवा तक लगभग 160 एकड़ भूमि अदानी-गूगल डेटा सेंटर परियोजना के लिए आवंटित की गई है। उन्होंने कहा कि यदि यह परियोजना लागू होती है तो आसपास की पहाड़ियों से आने वाला वर्षा जल मुदसलौवा जलाशय तक पहुंचने में बाधित हो सकता है, जिससे जलाशय की जल भंडारण क्षमता प्रभावित होगी और वार्ड-13 सहित आसपास के क्षेत्रों में पेयजल संकट उत्पन्न होने की संभावना है। शेख रहीमान ने कहा कि विशाखापट्टनम पहले से ही औद्योगिक गतिविधियों के कारण

वायु, ध्वनि और वाहन प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहा है। ऐसे में प्रस्तावित डेटा सेंटर से अरिलोवा क्षेत्र के पर्यावरण और स्थानीय लोगों के जीवन पर अतिरिक्त प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका सहित कई देशों में डेटा सेंट्रों के कारण प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभाव के खिलाफ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने तरलुवाडादृ मुदसलौवा तथा अनकापल्ली जिले के रामबिल्ली क्षेत्र में प्रस्तावित डेटा सेंटर परियोजनाओं के संबंध में स्थानीय लोगों से पर्याप्त परामर्श नहीं किया। सीपीआई नेता ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार परियोजना को पानी, बिजली जैसी बुनियादी



सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ बड़े पैमाने पर रियायतें दे रही है। उन्होंने कहा कि इससे सिंहाचलम पहाड़ियों, मुदसलौवा जलाशय और कबालकोंडा वन्यजीव अभयारण्य जैसे पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि लगभग 200 वर्ष पूर्व निर्मित मुदसलौवा

जलाशय आज भी अरिलोवा और आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए पेयजल का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसलिए इस जल स्रोत को प्रभावित करने वाली किसी भी परियोजना का जनता को विरोध करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अरिलोवा क्षेत्र पहले से ही पेयजल की कमी का सामना कर रहा है और बड़े डेटा सेंटर की स्थापना

से जल संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। उन्होंने सरकार से कॉरपोरेट हितों के बजाय जनता के हितों को प्राथमिकता देने की अपील की। कार्यक्रम में जिला समिति के सदस्य सी.एच. कासु बाबू, बी. पुष्पलता, के. लक्ष्मण राव, वैकटेश्वर राव, शंकर राव तथा शेख मदीना सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

माडुगुला में जन शिकायत निवारण कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू



माडुगुला, पेन पॉवर, 10 जुलाई : आंध्र प्रदेश सरकार के “एक माह दृ एक विधानसभा क्षेत्र दृ चार दौरे” अभियान के अंतर्गत जन शिकायत निवारण प्रणाली के दूसरे चरण का शुभारंभ शुक्रवार को माडुगुला स्थित पंचायत राज गेस्ट हाउस में

किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन माडुगुला विधायक बंडारू सत्यनारायण मूर्ति, अनकापल्ली जिला कलेक्टर विजय कृष्णन तथा संयुक्त कलेक्टर सौर्यमान पटेल की उपस्थिति में हुआ। इस पहल का उद्देश्य जनता की

शिकायतों का त्वरित एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना तथा प्रशासन को आम लोगों के और अधिक निकट लाना है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने अपनी समस्याओं एवं मांगों से संबंधित आवेदन अधिकारियों को सौंपे।

जिला कलेक्टर विजय कृष्णन, संयुक्त कलेक्टर सौर्यमान पटेल, प्रभारी जिला राजस्व अधिकारी (डीआरओ) वाई. श्रीनिवास राव तथा आरडीओ वी.वी. रमण ने स्वयं नागरिकों से आवेदन प्राप्त किए और संबंधित विभागों के माध्यम से शीघ्र एवं नियमानुसार समाधान का आश्वासन दिया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी भी उपस्थित रहे और अपने-अपने विभागों से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई की।



ट्रंप की वजह से अमेरिका-ईरान इस्लामाबाद समझौते को बचाना अब पहले से कहीं अधिक कठिन

अमेरिका और ईरान के बीच उस समझौते पर हस्ताक्षर हुए अभी एक महीना भी नहीं बीता था, जिसे पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने और व्यापक समझौते की नींव रखने वाला माना गया था। लेकिन अब अमेरिकी लड़ाकू विमान फिर से ईरान पर बमबारी कर रहे हैं। जवाब में ईरान खाड़ी देशों में अमेरिका से जुड़े ठिकानों पर हमले कर रहा है और वाणिज्यिक जहाजरानी को धमकी दे रहा है। होर्मुज जलडमरूमध्य और खाड़ी क्षेत्र के ऊपर मिसाइलें और ड्रोन उड़ रहे हैं। तेल की कीमतें बढ़ गई हैं और वैश्विक बाजारों में फिर से चिंता का माहौल लौट आया है। कल समाप्त हुए अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मानो इस समझौते की अंतिम विदाई की घोषणा कर दी। उन्होंने ईरान के साथ हुए समझौते के बारे में कहा, “जहां तक मेरा सवाल है, यह खत्म हो चुका है।” हालांकि कुछ ही घंटों बाद ट्रंप ने एयर फोर्स जन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ईरानी कार्रवाइयों ने “कुछ ही देर पहले” फोन किया था और वे किसी समझौते के लिए “बेहद उत्सुक” हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें यह नहीं पता कि वे ऐसे समझौते के योग्य हैं या नहीं। एक बार फिर दुनिया डोनाल्ड ट्रंप की सार्वजनिक और टीवी कैमरों के सामने होने वाली कूटनीति देख रही है। ताजा तनाव की शुरुआत होर्मुज जलडमरूमध्य के निकट तीन वाणिज्यिक जहाजों पर हुए

हमलों के बाद हुई, जिनके लिए वाशिंगटन ने ईरान को जिम्मेदार ठहराया। अमेरिका की प्रतिक्रिया बेहद आक्रामक रही। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार, मंगलवार को लगभग 80 ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए और गुरुवार तड़के दूसरे चरण में लगभग 90 अतिरिक्त लक्ष्यों को निशाना बनाया गया। अमेरिका का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य होर्मुज जलडमरूमध्य में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक नाविकों को खतरा पहुंचाने की ईरान की क्षमता को कमजोर करना था। **रुस्रु ‘धोंस और वादाखिलाफी’** दूसरी ओर ईरान भी उत्तना ही आक्रामक रुख अपनाए हुए है। ईरानी संसद अध्यक्ष और अमेरिका के साथ वार्ता में शामिल प्रमुख नेता मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने कहा कि अमेरिका अब तक यह नहीं समझ पाया है कि “धोंस जमाने और वादाखिलाफी करने की कीमत चुकानी पड़ती है।” ईरान के विदेश मंत्री ने ट्रंप की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तेहरान अशिष्ट भाषा से नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई से जवाब देगा। बहरीन में विस्फोटों की खबरें आई हैं। कुवैत ने दावा किया है कि उसने मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराया है। कतर ने सुरक्षा चेतावनी जारी की है। यह घटनाक्रम किसी कमजोर युद्धविराम के मामूली उल्लंघन जैसा नहीं दिखता। पश्चिम एशिया एक बार फिर तनाव और संघर्ष की सीढ़ियां चढ़ता दिखाई दे रहा है। फिर भी इस्लामाबाद समझौते

को पूरी तरह समाप्त घोषित करना जल्दबाजी होगी। ट्रंप के हालिया बयानों को गंभीरता से लेना जरूरी है। वह अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जिसने हाल ही में अपनी 250वीं वर्षगांठ धूमधाम और शक्ति प्रदर्शन के साथ मनाई है। अंकारा में उन्होंने ईरान के नेताओं को “गंदे लोग” और “बीमार मानसिकता वाले लोग” कहा। उनका संकेत था कि तेहरान से बातचीत करना समय की बर्बादी हो सकती है। उन्होंने ईरान के तेल निर्यात के प्रमुख केंद्र खरग द्वीप पर नियंत्रण करने की संभावना का भी उल्लेख किया। **रुस्रु ट्रंप की कूटनीतिक भाषा** ट्रंप ने कूटनीति की भाषा को पूरी तरह बदल दिया है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति भी धमकियां देते थे, प्रतिबंध लगाते थे और कभी-कभी सरकारों को गिराने तक की कोशिश करते थे, लेकिन वे सार्वजनिक मंचों पर अपने शब्दों का चयन सावधानी से करते थे। ट्रंप ऐसा नहीं करते। पिछले वर्ष व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के साथ उनकी बहुचर्चित बैठक इसका उदाहरण थी। एक कूटनीतिक मतभेद कैमरों के सामने खुली बहस में बदल गया। जो बातें आमतौर पर बंद कमरों में कही जाती थीं, वे सार्वजनिक रूप से कही जाने लगीं। ईरान ट्रंप के साथ पर्याप्त समय तक ट्विटर का चक्कर खा चुका है और उसकी शैली को समझता है। यही वह अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने कभी तेहरान में शासन परिवर्तन की बात की और फिर

उसी सरकार के साथ बातचीत करनी जल्दबाजी होगी। समझौते को लगभग मृत घोषित करने के बावजूद ट्रंप ने स्वीकार किया कि उनके विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर अभी भी कूटनीतिक प्रक्रिया में शामिल हैं। रुस्रु क्या युद्धविराम समाप्त हो गया? तो क्या यह समझौता वास्तव में खत्म हो चुका है? संभव है। लेकिन दोनों देशों के बीच संवाद के रास्ते पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। तेहरान का भी यही विरोधाभासी रुख है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने उसके तेल व्यापार पर फिर से दबाव बनाकर और ईरानी क्षेत्र पर हमले करके समझौते का उल्लंघन किया है। ईरान ने यह भी कहा है कि लेबनान में इजराइल की सैन्य कार्रवाई जारी है, जबकि समझौते के अनुसार उसे दक्षिणी लेबनान से हटना था। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका ने समझौते के तहत किए गए कई महत्वपूर्ण वादों को पूरा नहीं किया। समझौते के पाठ के अनुसार अंतिम समझौता होने तक अमेरिका को नए प्रतिबंध नहीं लगाने थे और ईरानी तेल निर्यात से संबंधित छूट जारी रखनी थी। दोनों पक्षों को यथार्थ्यति बनाए रखने की भी शर्त थी। फिर भी ईरान ने औपचारिक रूप से इस समझौते को समाप्त घोषित नहीं किया है। क्यों? क्योंकि तमाम गुस्से और अविश्वास के बावजूद तेहरान शायद कूटनीति की एक छोट्टी-सी खिड़की खुली रखना



चाहता है। हालांकि अब सबसे बड़ी चिंता यह है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर शुरु हुआ विवाद एक और अधिक खतरनाक मुद्दे में बदलता जा रहा हैकुहोर्मुज जलडमरूमध्य। यदि यह संघर्ष और बढ़ता है, तो इसका प्रभाव केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और विश्व अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर असर पड़ सकता है। **होर्मुज का दांव** ऐसा प्रतीत होता है कि ईरान ने इस युद्ध से एक महत्वपूर्ण रणनीतिक सबक सीखा है। हाल के महीनों में उसने यह साबित किया है कि उसके लिए होर्मुज जलडमरूमध्य शायद परमाणु बम से भी अधिक उपयोगी हथियार साबित हो सकता है। परमाणु हथियार बनाना कठिन

है। यदि वह चाहे तो कुछ समय के लिए इसे बंद भी कर सकता है। क्या यह एक असाधारण रूप से शक्तिशाली हथियार नहीं है? अब ऐसा लगता है कि तेहरान होर्मुज जलडमरूमध्य में एक नई वास्तविकता स्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। ईरानी नेताओं ने इस समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाजों पर अटिाक नियंत्रण की बात कही है। यहां तक कि जहाजों से मार्ग उपयोग के लिए शुल्क लेने की संकेत भी चर्चा हुई है। वॉशिंगटन ऐसे किसी भी प्रस्ताव को आसानी से स्वीकार नहीं करेगा। यदि होर्मुज पर ईरान का प्रभाव बढ़ता है तो उसे केवल अमेरिका पर ही नहीं, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाने की क्षमता मिल जाएगी। **ट्रंप की रणनीति** ईरान के तेल ढांचे, विशेष रूप से खरग द्वीप, के खिलाफ ट्रंप की धमकियों को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। ईरान तेल को जमीन पर भंडारित कर सकता है। वह तेल से भरे टैंकरों को समुद्र में खड़ा रख सकता है। लेकिन यह व्यवस्था अनिश्चितकाल तक नहीं चल सकती। किसी न किसी समय उसे अपना तेल बेचना ही होगा। अमेरिका की रणनीति स्पष्ट दिखाई देती हैकुलाभ बाजारों में गिरावट आ जाती है। दुनिया की लगभग पांचवां हिस्सा तेल और गैस आपूर्ति इसी संकरे समुद्री मार्ग से गुजरती है। ईरान को अमेरिका को सैन्य रूप से हराने की आवश्यकता नहीं है। वह केवल इस जलडमरूमध्य को अस्थिर और अनिश्चित बनाकर भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा सकता

है। वह पूरे क्षेत्र को इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर सकता है। बहरीन, कुवैत और क्षेत्र के अन्य देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों के खिलाफ हमले और धमकियां इस बात का संकेत हैं कि तेहरान संघर्ष को व्यापक क्षेत्रीय युद्ध में बदलने की क्षमता रखता है। ईरान अमेरिका की सैन्य शक्ति की बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन उसे इसकी आवश्यकता भी नहीं है। उसके लिए इतना पर्याप्त है कि वह युद्ध को महंगा, अनिश्चित और क्षेत्रीय बना दे। **खाड़ी देशों की दुविधा** यह स्थिति खाड़ी देशों के लिए बेहद चिंताजनक है। इनमें से अधिकांश देश अमेरिका के सहयोगी हैं और वहां अमेरिकी सैन्य अड्डे मौजूद हैं। खाड़ी क्षेत्र का कोई भी देश एक ओर लंबे युद्ध की इच्छा नहीं रखता। पिछले दशक में इस क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर जैसे देश अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वैश्विक वित्त, नए शहरों, पर्यटन, खेल और तेल के बाद की अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उनकी राजधानियों के ऊपर उड़ती मिसाइलें इस विकास और निवेश की कहानी के अनुकूल नहीं हैं। ईरानी नेतृत्व इस कमजोरी का पूरा लाभ उठाने का प्रयास कर रहा है। इसीलिए आने वाले समय में एक और व्यापक कूटनीतिक प्रयास देखने को मिल सकता है। कतर पहले भी मध्यस्थ की भूमिका निभा चुका है। ओमान को शांत और प्रभावी कूटनीति का दशकों का अनुभव है।

'छावा' डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर के साथ फिल्म करेंगे ऋतिक रोशन?



बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन के फैंस के लिए एक बेहद एक्साइटिंग खबर सामने आ रही है. 'छावा' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर ने अपनी अगली फिल्म के लिए ऋतिक रोशन को अप्रोच किया है. फिलहाल ऋतिक के पास 'कृष 4', रजनीकांत की 'जेलर 2' (कैमियो) और होंबाले फिल्मस का एक बड़ा प्रोजेक्ट है.

बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन को फिर से दमदार अंदाज में जलवा बिखेरते देखने का फैंस का इंतजार लंबा ही होता जा रहा है. पिछले साल आई उनकी स्पाई-यूनियर्स की फिल्म वॉर 2 उम्मीद से ठीक उलट बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई. तभी से फैंस उनकी नई फिल्मों का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं. अब ऋतिक फैंस के लिए एक एक्साइटिंग खबर है. चर्चा है कि छावा के डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर ने ऋतिक को अपनी नई फिल्म के लिए अप्रोच किया है.

ऋतिक को डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर ने अपनी नई फिल्म के लिए अप्रोच किया है. इस फिल्म के बारे में ज्यादा डिटेल्स सामने नहीं आई हैं, मगर इतना जरूर सामने आया है कि ऋतिक को अभी इस प्रोजेक्ट पर अपनी रजामंदी देनी है.

'लुका छुपी', 'मिमी' और 'जरा हटके जरा बचके' जैसी कामयाब स्मॉल-टउन स्टोरीज के बाद लक्ष्मण ने विक्की कौशल के साथ

एक्टर राजेश शर्मा बीमार, तेलंगाना सीएम से जांच की मांग

एक्टर गंभीर हालत में भर्ती; वर्कर्स एसोसिएशन ने पूछा- तुरंत अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया

ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने प्रभास स्टारर फिल्म 'फौजी' के सेट पर एक्टर राजेश शर्मा के साथ हुई घटना की हाई-लेवल जांच की मांग की है। एसोसिएशन ने इस मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से दखल देने की अपील की है ताकि सेट पर लापरवाही की जांच हो सके।

दरअसल, हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में शूटिंग के दौरान अभिनेता राजेश शर्मा को एक जहरीले कीड़े ने काट लिया था, जिससे उनके पैर का इन्फेक्शन घुटने तक फैल गया और उन्हें कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टर के मुताबिक राजेश शर्मा अभी खतरे से बाहर नहीं हैं।

सीएम रेवंत रेड्डी से दखल देने की मांग

ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने फिल्म 'फौजी' के सेट पर हुई इस घटना की तुरंत और पारदर्शी जांच कराने की मांग उठाई है। एसोसिएशन ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को पत्र लिखकर मामले की गहराई से जांच कराने की अपील की है। एसोसिएशन का कहना है कि उन हालातों का पता लगाया जाना चाहिए जिनकी वजह से एक्टर राजेश शर्मा की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक राजेश शर्मा की हालत अभी स्थिर है, लेकिन संक्रमण काफी गंभीर बना हुआ है।

हैदराबाद के अस्पताल में क्यों नहीं कराया भर्ती?

एसोसिएशन ने फिल्म की प्रोडक्शन टीम की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पूछा कि जब सेट पर शूटिंग के दौरान एक्टर की हालत इतनी गंभीर हो गई थी, तो उन्हें तुरंत हैदराबाद के ही किसी बड़े अस्पताल में इलाज के लिए क्यों नहीं ले जाया गया। अधिकारियों को इस बात की जांच करनी चाहिए कि प्रोडक्शन टीम ने तय सुरक्षा, साफ-सफाई और इमरजेंसी मेडिकल नियमों का पालन किया था या नहीं। फिल्म इंडस्ट्री की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वह सभी कलाकारों और क्रू मेंबर्स को सुरक्षित माहौल दे।

इलाज का पूरा खर्च उठाएं फिल्म के प्रोड्यूसर्स

एसोसिएशन ने मांग की है कि फिल्म 'फौजी'



के प्रोड्यूसर्स राजेश शर्मा के इलाज का पूरा खर्च उठाएं। उन्हें तब तक सबसे बेहतर मेडिकल सुविधाएं दी जाएं जब तक वे पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते। एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि कई शूटिंग सेट पर साफ-सफाई और इमरजेंसी हेल्थकेयर से जुड़ी लापरवाही की बातें सामने आती रही हैं। नौकरी जाने के डर से क्रू मेंबर्स और वर्कर्स अक्सर इन मुद्दों पर खुलकर बात नहीं कर पाते हैं। अगर इस मामले में कोई लापरवाही साबित होती है, तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।

सेट पर पैकअप के बाद हुआ हादसा

सुदीपा चटर्जी के सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक यह घटना हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में हुई। राजेश शर्मा वहां प्रभास की आने वाली फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग खत्म होने के बाद वे सेट के पास पेड़-पौधों वाले इलाके में लोकल टेक्नीशियन्स के साथ बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें पैर में किसी कीड़े या जहरीली मकड़ी ने काट लिया। उस समय मामला गंभीर नहीं लगा, इसलिए उन्होंने तुरंत कोई मेडिकल मदद नहीं ली और काम जारी रखा।

प्लाइट में अचानक बह गया बुखार

कीड़े के काटने के करीब छह घंटे बाद राजेश शर्मा के दाहिने पैर में तेज दर्द शुरू हो गया और उनकी तबीयत खराब होने लगी।

इसके बाद भी उन्होंने कोलकाता के लिए फ्लाइट पकड़ी।

सफर के दौरान उन्हें तेज बुखार आ गया और वे काफी बेचैन हो गए। कोलकाता पहुंचने पर अगले दिन उनकी हालत ज्यादा बिगड़ गई। इसके बाद परिवार ने उन्हें तुरंत ढाकुरिया के मनपाल अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में भर्ती हुए एक दिन से ज्यादा का समय हो चुका है।

पैर में छाले पड़े, फेफड़ों में ब्लॉट का खतरा

अस्पताल के डॉक्टर अभिजीत भट्टाचार्य ने बताया कि कीड़े का इन्फेक्शन पैर के अंगुठे से लेकर घुटने तक फैल गया है। प्रभावित हिस्से पर बड़े-बड़े छाले पड़ गए हैं। डॉक्टर के मुताबिक अभी स्थिति के बारे में साफ तौर पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।

राजेश शर्मा को डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में रखा गया है। डॉक्टरों को चिंता है कि इन्फेक्शन की वजह से ब्लड क्लॉट (खून का थक्का) बन सकता है। अगर यह क्लॉट फेफड़ों तक पहुंचता है, तो जान का खतरा हो सकता है।

जाह्नवी कपूर की मेहंदी में दिखा बॉयफ्रेंड का नाम:निकनेम 'शिखु' ने खींचा ध्यान

अंशुला कपूर के वेंडिंग रिसेशन में जाह्नवी कपूर अपने लुक के साथ-साथ मेहंदी को लेकर भी चर्चा में रहीं। उन्होंने डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की सिल्क साड़ी को स्ट्रैपलेस ब्लाउज के साथ पहना था। उनका यह लुक सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया गया।

जाह्नवी ने इंस्टाग्राम पर रिसेशन की कई तस्वीरें शेयर कीं। इन तस्वीरों में उनकी मेहंदी पर 'शिखु' नाम लिखा नजर आया। 'शिखु' उनके बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया का निकनेम है। यह नाम मेहंदी के डिजाइन में बारीकी से लिखा गया था।

रिसेशन में जाह्नवी कपूर ने लैवेंडर रंग की बनारसी सिल्क साड़ी के साथ रॉयल लुक कैरी किया। वहीं, अंशुला कपूर के वेंडिंग रिसेशन में जाह्नवी कपूर का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें उन्होंने डोल बनाया।

हाल ही में नाइटसूट की तस्वीर वायरल हुई

बता दें कि 2024 में फिल्म 'मैदान' की स्क्रीनिंग के दौरान वह 'शिखु' नाम का नेकलेस पहनकर पहुंची थीं। गौरतलब है कि हाल ही में सोशल मीडिया पर जाह्नवी की एक तस्वीर सामने आई थी, जिसमें वे एक



अनोखा नाइटसूट पहने नजर आ रही हैं। इस नाइटसूट पर शिखर पहाड़िया के नाम का एक मैसेज भी लिखा था।

इस फोटो में जाह्नवी ने पिंग कलर का नाइटसूट और ग्रे जैकेट पहना हुआ था। उनके नाइटसूट पर अंग्रेजी में लिखा है, 'इफ लॉस्ट, प्लीज रिटर्न टू शिखर पहाड़िया' यानी 'अगर गुम हो जाऊं, तो कृपया शिखर पहाड़िया के पास लौटा दें।

‘मैं एक कार्ड लूंगा और उसे हरा रंग दूंगा’, अमेरिकी नागरिकता पर दिलजीत दोसांझ ने दी प्रतिक्रिया

दिलजीत दोसांझ इन दिनों अपनी फिल्म 'सतलुज' को लेकर चर्चाओं में हैं। इस बीच एक बार फिर अपनी नागरिकता को लेकर भी एक्टर-सिंगर सुर्खियों में हैं। मई में ऐसी खबरें सामने आई कि दिलजीत दोसांझ ने 2022 में अमेरिकी नागरिकता ले ली थी। तब से सिंगर ने इस मामले पर चुपनी साधे रखी है। हालांकि, हाल ही में फैंस के साथ बातचीत के दौरान दिलजीत से उनकी नागरिकता के बारे में पूछा गया। उन्होंने सीधा जवाब देने के बजाय, फैंस के साथ इस अटकलबाजी पर मजाक-मजाक में बात की।

दुनिया का झग़ा कभी खत्म नहीं होगा

इंस्टाग्राम लाइव के दौरान एक प्रशंसक ने सुझाव दिया कि दिलजीत को अपनी फिल्म सतलुज के जी5 ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटाए



जाने के बाद अमेरिकी ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करना चाहिए। प्रशंसक को जवाब देते हुए दिलजीत ने कहा, 'मैं एक कार्ड लूंगा और उसे हरा रंग दूंगा। मैं कुछ नहीं कह रहा।

सब छोड़कर ये खबर बन जाएगी। ऐसा नहीं होता। दुनिया का झग़ा कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन मेरा मानना है कि हर किसी को बिना बीजा के किसी भी देश की यात्रा करने की अनुमति होनी चाहिए। पूरी दुनिया को एक होना चाहिए। मैं ठीक हूँ, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, है ना ?'

आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं?

एक अन्य लाइव बातचीत में एक फैन ने मजाक में दिलजीत से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से बात करने और सभी को अमेरिकी नागरिकता दिलाने में मदद करने का

अनुरोध किया। दिलजीत ने इस अनुरोध पर हंसते हुए कहा, 'आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? मैं तो बस एक कलाकार हूँ।

मैं उनसे नागरिकता के मुद्दे सुलझाने के लिए कैसे कह सकता हूँ? उनकी बेटी मुझे फॉलो करती है, लेकिन मैंने उससे भी कभी बात नहीं की। मैं कभी किसी से कोई एहसास नहीं मांगता। अगर कुछ होना तय है, तो हो जाता है। अगर नहीं होना है, तो नहीं होता।'

दिलजीत ने 2022 में अमेरिका की नागरिकता ली थी। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि सिंगर की पत्नी, संदीप कौर, अमेरिकी नागरिक हैं। इसमें यह भी बताया गया था कि दिलजीत ने कैलिफोर्निया के एक पॉश इलाके में बने पांच बेडरूम वाले बंगले को अपना घर बताया था।

मीरा कपूर ने दिखाया अपना 'हेल्थ बार', बताया कैसे बच्चों को लगा रही हेल्दी स्नैकिंग की आदत

एंटरप्रेन्योर और शाहिद कपूर की पत्नी मीरा कपूर ने एक बार फिर अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल की झलक सोशल मीडिया पर साझा की है। मीरा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने अपने घर के एक खास कोने को दिखाया। इस जगह को उन्होंने 'हेल्थ बार' बताया। यह हेल्थ बार उनके बच्चों के स्नैक काउंटर के ठीक बगल में बनाया गया है, ताकि घर के सभी लोग आसानी से पौष्टिक चीजें चुन सकें। वीडियो के साथ मीरा ने लिखा कि वह काफी समय से ऐसा हेल्थ बार बनाना चाहती थीं। आखिरकार उन्होंने किचन की दराजों में रखे नट्स, सीड्स, सुपरफूड्स और हेल्दी पाउडर को बाहर निकालकर एक खूबसूरत और व्यवस्थित शेल्फ पर सजा दिया। उनका मानना है कि जब हेल्दी चीजें सामने दिखाई देती हैं तो उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाना आसान हो जाता है। उन्होंने कहा कि जो उन्हें घर पर बने हेल्दी स्नैक्स भजते हैं, अब उनके हेल्थ बार को दोबारा भरने का समय आ गया है। वीडियो में मीरा अपने फॉलोअर्स को हेल्थ बार का पूरा सेटअप दिखाती हैं। वह बताती हैं कि उन्होंने इसे खासतौर पर बच्चों और परिवार की स्नैकिंग हैबिट्स को बेहतर बनाने के लिए तैयार किया है। उनके मुताबिक, हर घर में शाम करीब चार बजे बच्चों का एक ही सवाल होता है मम्मा, भूख लगी है, क्या खा सकते हैं? ऐसे में अगर हेल्दी स्नैक्स आसानी से नजर आ जाएं, तो बच्चे भी उन्हें चुनने लगते हैं।

मीरा का कहना है कि अक्सर डाई फूड्स, सीड्स और हेल्दी स्नैक्स के पैकेट किचन की अलमारियों या पेंड्री में कहीं पीछे रखे रह जाते हैं। नतीजा यह होता है कि लोग उन्हें भूल जाते हैं और उनकी जगह अनहेल्दी स्नैक्स खा लेते हैं। इसी वजह से उन्होंने सभी चीजों को पारदर्शी जार



फिल्म राजनीति के बजाय मानवीय रिश्तों और दर्द को दिखाती है।

'बंटवारा 1947' की स्टार कास्ट

इस फिल्म का नाम पहले 'लाहौर 1947' था। अब इस फिल्म का नाम 'बंटवारा 1947' कर दिया गया है। इसमें सनी देओल, प्रीति जिंटा, मशहूर संगीतकार एआर रहमान ने अपनी आने वाली फिल्म 'बंटवारा 1947' के एक गाने के लिए सिंगर सोनू निगम के साथ काम किया है। रहमान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी खुशी जाहिर की है।

रहमान ने की सोनू की तारीफ

फिल्म 'बंटवारा 1947' के गाने 'ओह तबस्सुम' को सोनू निगम ने गाया है। एआर रहमान ने एक्स हँडल पर सोनू की जमकर तारीफ की है। रहमान ने सोनू से पूछा, 'भाई, गाते समय अपनी आवाज में इतना रोमांस कैसे ले आते हो।'

तया है 'बंटवारा 1947' की कहानी

'बंटवारा 1947' असगर वजाहत के मशहूर नाटक 'जिस लाहौर नई देख्या, ओ जम्माई नई' पर आधारित है। कहानी देश के बंटवारे के समय एक हिंदू परिवार की है, जिसे लाहौर आना पड़ता है। वहां उन्हें एक हवेली मिलती है, जहां पहले से ही एक बुजुर्ग मुस्लिम महिला रह रही होती है। यह